लोकसभा सचिवालय

लोकसभा संख्या: 18 सत्र संख्या: VIII

27.07.2026

<u>नियम 377 के अधीन मामला</u>

ग्रामीण भारत के लिए खास तौर पर बनाई गई भारतनेट परियोजना योजना के बावजूद, छत्तीसगढ़ के लगभग 20000 गाँवों में रहने वाले करोड़ों लोगों को अभी तक भी इन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस परियोजना के पहले चरण में, 4114 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई थी, लेकिन इनमें से 3519 ग्राम पंचायतों में कनेक्शन बंद या बेकार पड़े हैं, और सिर्फ़ 595 ही चालू हालत में हैं। दूसरे चरण में, 1,754 करोड़ रुपये की भारी लागत से 5,540 ग्राम पंचायतों में OFC बिछाई गई थी। अभी, इनमें से एक भी ग्राम पंचायत काम नहीं कर रही है। चिप्स छत्तीसगढ़ और कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच बिल भुगतान के विवाद कारण यह इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संशोधित भारतनेट प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ के लिए अतिरिक्त ₹3,942 करोड़ मंज़ूर किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की डिजिटल इंडिया की भावना को साकार करने हेतु एक आवश्यक मॉनिटरिंग कमिटी का गठन करके पुराने कार्यों की समीक्षा एवं नए फण्ड के सफल क्रियान्वन बहुत ही महत्वूर्ण हो जाता है। देश के गाँव ही देश का भविष्य है अतः सभी ग्रामीणवासियों को यह मूलभूत सुविधा का अभिगम होना ज़रूरी है।

बृजमोहन अग्रवाल
भारतीय जनता पार्टी
पहचान पत्र संख्या: 89
विभाजन संख्या: 157